संपादकीय जागरण

शुक्रवार, 27 जुलाई, 2018 : आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा वि. 2075

विनम्रता शीघ्र उन्नति की चाबी है

बारिश के बाद बदहाली

ठीक-ठाक बारिश के बाद दिल्ली और आसपास के शहरों में जन-जीवन जिस बुरी तरह प्रभावित हुआ उसी तरह लगभग सारे देश और खासकर शहरी इलाकों में देखने को मिल रहा है। जब भी कहीं बेहतर बारिश हो जाती है, जल भराव के कारण एक तरह की नारकीय स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसा बारिश के कारण नहीं, बल्कि शहरों के दुर्दशाग्रस्त ढांचे के कारण होता है। बारिश के पानी की निकासी न होने के कारण केवल सड़कें ही जलमग्न नहीं होतीं, लोगों के घरों में बरसाती और कभी-कभी तो सीवर का पानी भी घुस जाता है। अक्सर वैध-अवैध तरीके से बनीं जर्जर इमारतें गिरने का भी खतरा पैदा हो जाता है। कई बार तो वे जनहानि का कारण भी बन जाती हैं। बारिश के बाद यातायात के साथ अन्य कई व्यवस्थाएं भी प्रभावित होती हैं। कहीं बिजली आपूर्ति लंबे समय के लिए बाधित हो जाती है तो कहीं पीने के पानी की आपूर्ति ठप हो जाती है। अब तो शहरों के नए इलाके भी दुर्दशा बयान करने लगे हैं। शहरी जीवन बारिश की प्रतीक्षा करने के साथ ही उसे लेकर आशंकित रहने लगा है तो इन्हीं कारणों से। सामान्य से थोड़ी ज्यादा बारिश के बाद अगर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे बड़े और नामी शहर बदहाली की कहानी कहने लगते हैं तो इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है कि अन्य शहरों की कैसी दुर्गति होती होगी? अगर बारिश के बाद दिल्ली और मुंबई की तरह से अन्य शहरों की बदहाली राष्ट्रीय खबरों का हिस्सा नहीं बनती तो इसका यह मतलब नहीं कि वहां सब कुछ ठीक रहता है।

यह किसी राष्ट्रीय संकट से कम नहीं कि जब शहरों को संवारने अथवा उन्हें स्मार्ट सिटी में तब्दील करने की बड़ी-बड़ी बातें हो रही हैं और किस्म-किस्म की योजनाएं भी चल रही हैं तब बारिश के दौरान वे रहने के काबिल नहीं दिखते। एक बड़ी संख्या में लोग शहरों को अपना ठिकाना इसलिए बनाते हैं ताकि बेहतर और सुविधायुक्त जीवन जी सकें, लेकिन वहां उन्हें समस्याओं के अंबार देखने को मिलते हैं-चाहे वे टैक्स देने वाले हों या फिर न देने वाले। यह तब हो रहा है जब शहरी ढांचे का निर्माण और उसका रख-रखाव करने वाले विभागों की बजट बढ़ता जा रहा है। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि ये सारे विभाग अवैध या फिर अनियोजित विकास का उदाहरण पेश करने की होड़ में शामिल हो गए हैं और कोई भी उन्हें रोकने-टोकने वाला नहीं। यदि नगर नियोजक, इंजीनियर, वास्तुविद वगैरह बारिश के पानी की निकासी की भी सही व्यवस्था नहीं कर सकते तो फिर वे किस काम के? शहरों के ढांचे को दुरुस्त बनाए रखने में तब लापरवाही का परिचय दिया जा रहा है जब हमारे नीति-नियंता यह अच्छे से जान रहे हैं कि आने वाले समय में ग्रामीण इलाकों से शहरों में आबादी के आने की रफ्तार और तेज होने वाली है। यह देखना दयनीय है कि जब भारत जैसे अन्य देश अपने शहरों को विकास के इंजन के रूप में देख रहे हैं और इसी रूप में उनकी देख-भाल कर रहे हैं तब अपने देश में वे बदहाली का नमूना बन रहे हैं।

नागरिकों के साथ धोखा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उन लाखों नागरिकों के प्रति फिक्र पूरी तरह जायज और जरूरी है जिनकी गाढ़ी कमाई का पैसा रियल एस्टेट कारोबारियों की धोखाधड़ी में फंसा है। इन कारोबारियों ने नियम-कानून ताख पर रखकर न सिर्फ बड़े-बड़े अवैध अपार्टमेंट और व्यावसायिक काम्प्लेक्स खड़े किए बल्कि झांसा देकर नागरिकों को बेच भी दिए। चूंकि ये निर्माण पूरी तरह नियमविरुद्ध हैं लिहाजा सरकारी एजेंसियां वहां नागरिक सुविधाएं विकसित नहीं कर रहीं। मुख्यमंत्री का इन हालात पर चिंतित होना लाजिमी है। उनका यह फैसला महत्वपूर्ण है कि अवैध ढंग से आवासीय कॉलोनियां बनाने वाले बिल्डर ही वहां नागरिक सुविधाओं का विकास करें। उनका यह कथन महत्वपूर्ण है कि नियमविरुद्ध कार्य करने वाले बिल्डरों के खिलाफ ऐसी नजीर कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में कोई नागरिकों से धोखाधड़ी करने की जुर्रत न करे।

> बिल्डरों को इनके द्वारा अवैध ढंग से निर्मित कॉलोनियों में निर्धारित समयावधि में जरूरी सुविधाओं के विकास को बाध्य किया जाना चाहिए।

उम्मीद है कि शासन-प्रशासन ने मुख्यमंत्री की मंशा सही अर्थ में समझी होगी और धोखाधड़ी करने वाले बिल्डरों पर जल्द ही शिकंजा कसेगा। इन बिल्डरों को इनके द्वारा अवैध ढंग से निर्मित कॉलोनियों में निर्धारित समयावधि में जरूरी सुविधाओं के विकास के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। यह कार्रवाई सिर्फ राजधानी के बजाय सूबे के सभी शहरों में की जानी चाहिए। यह देखा जाना जरूरी है कि कायदा-कानून की अनदेखी करके इतने बड़े निर्माण कार्य कैसे हुए। संभव है कि इसकी वजह रियल एस्टेट कारोबारियों और सरकारी निगरानी तंत्र की भ्रष्टाचार आधारित दुरभि संधि रही हो, यद्यपि गहन जांच हुए बगैर इसका पर्दाफाश होना कठिन है।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या घूस देने को भी अपराध बनाए जाने से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा?

आज का सवाल
क्या अदालती कार्यवाही के सीधे प्रसारण से न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y, N** या **C** लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, **N**-नहीं, **C**-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।
सभी आंकड़े प्रतिशत में।

इमरान खान से बेहतरी की उम्मीद नहीं

विवेक काटजू

यह तय है कि तमाम राजनीतिक ड्रामे के साथ इमरान खान कुछ नया करते दिखेंगे, लेकिन इसमें संदेह है कि उसमें कुछ सार्थकता भी होगी

पाकिस्तान तहरीके इंसाफ यानी पीटीआई के प्रमुख इमरान खान पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बनने को तैयार हैं। हालांकि पाकिस्तान चुनाव आयोग की वेबसाइट के नाकाम हो जाने के कारण चुनाव नतीजों की आधिकारिक घोषणा होने में देर हो रही है, लेकिन इन पंक्तियों के लिखे जाने तक सामने आए नतीजों के हिसाब से इमरान की पार्टी सबसे बड़े दल के तौर पर उभर आई है। भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में कैद पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग (एन) दूसरे और आसिफ अली जरदारी एवं बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी तीसरे स्थान पर रही। एक बड़ी संख्या में छोटी पार्टियों के उम्मीदवार और निर्दलीय भी नेशनल असेंबली यानी पाकिस्तानी संसद पहुंचने में सफल रहे हैं। जाहिर है कि वे इमरान खान का समर्थन करने के लिए तैयार होंगे। यह काम पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी भी कर सकती है। इस तरह इमरान खान को करीब दो दशक पुराने अपने सपने को साकार करने में आसानी होगी। हालांकि जब इमरान अपना दल बनाकर राजनीति में कूदे थे तब और उसके बाद भी वह सियासत के प्रति संजीदा नहीं दिखते थे। उन्हें गंभीर राजनेता के तौर पर देखा भी नहीं जाता था। यह सच है कि उनकी राजनीतिक सफलता में सेना का सहयोग है, लेकिन उसकी ओर से कहा यही जाएगा कि उसका पाकिस्तान की राजनीति से कोई लेना-देना नहीं। सेना कुछ भी कहे, हकीकत यही है कि वह पाकिस्तान के सबसे ताकतवर नेता नवाज शरीफ को राजनीतिक तौर पर खत्म करने पर तुली थी।

राजनीतिक रूप से पाकिस्तान के सबसे अहम राज्य पंजाब को नवाज शरीफ का गढ़ माना जाता है। पाकिस्तानी सेना को यह पसंद नहीं कि देश की सुरक्षा एवं विदेश नीति के साथ-साथ भारत संबंधी नीति को कोई नेता अपने हिसाब से चलाए। बतौर प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ऐसा ही करना चाहते थे और वह इसे अपना संवैधानिक अधिकार भी समझते थे। सेना को नवाज शरीफ के पर कतरने का मौका 2016 में तब मिला जब पनामा पेपर्स मामले में यह सामने आया कि उनके परिवार के लोगों की विदेश में संपत्ति और व्यवसाय है। इसी के बाद वह सेना और अदालतों की घेरेबंदी में आ गए। पहले तो उन्हें राजनीतिक पद धारण करने के अयोग्य ठहराया गया और फिर उन्हें और उनकी बेटी को भ्रष्टाचार के आरोप में सजा सुना दी गई। राजनीतिक शहादत दिखाने के इरादे से नवाज शरीफ गिरफ्तारी के खतरे के बावजूद बेटी के साथ पाकिस्तान लौटे। उन्हें विमान से सीधे जेल भेज दिया गया और चुनाव प्रचार के दौरान जमानत पर बाहर नहीं आने दिया गया। इसके बाद उनके कई सहयोगी और समर्थक इमरान खान के पाले में चले गए। ऐसा इसलिए भी हुआ, क्योंकि सेना की ऐसी ही मंशा थी। इसके बाद भी तमाम लोग नवाज के साथ खड़े रहे। शायद इसी कारण नेशनल असेंबली के साथ हुए विधानसभा चुनावों में नवाज की पार्टी अपने गढ़ पंजाब को बचाने में सफल रही। इसके बावजूद इस पर यकीन करना कठिन है कि सेना नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ या उनके परिवार के किसी अन्य सदस्य को पंजाब का मुख्यमंत्री बनने देगी। यह भी उल्लेखनीय है कि जहां शहबाज चुनाव हार गए वहीं उनका बेटा हमजा जीत हासिल करने में समर्थ रहा।

अवधेश राजपूत

इसमें दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने की तैयारी कर रहे इमरान खान अपने गढ़ खैबर पख्तूनख्वा में अपना जनाधार बढ़ाने में सफल रहे। इस प्रांत में उनकी पार्टी 2013 से सत्ता में है, लेकिन जब तक उनका सिक्का पंजाब में नहीं चलता वह पाकिस्तान के वैसे ताकतवर नेता नहीं बन सकते जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो थे। सबसे बड़ी पार्टी का नेता बनने के बाद भी उनका राजनीतिक कद नवाज शरीफ जैसा नहीं है। वह तो इसलिए बढ़त हासिल करने में कामयाब रहे, क्योंकि सेना उनके साथ थी और न्यायपालिका ने नवाज शरीफ को जेल भेज दिया। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि इमरान को जहां पंजाब में अपेक्षित समर्थन नहीं मिला वहीं सिंध में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सरकार बनाने जा रही है।

अब जब पाकिस्तान में नई सरकार बनने जा रही है तब सबसे अहम सवाल यह है कि आर्थिक और सामाजिक मोर्चे पर गंभीर समस्याओं से दो-चार यह पड़ोसी देश किस रास्ते पर जाएगा? पाकिस्तान में अतिवाद उफान पर है तो आतंकवाद भी बेलगाम ही है। खूंखार आतंकी संगठन लश्करे तैयबा ने राजनीति की भी राह पकड़ ली है। चिंता की बात यह है कि इमरान खान ऐसे संगठनों के प्रति हमदर्दी रखते हैं। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान नया पाकिस्तान के नाम पर वोट मांगे, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान की सोच-समझ में व्यापक बदलाव जरूरी है। अपनी विचारधारा बदलने और भारत से हर क्षेत्र में बराबरी करने के इरादे से मुक्त होकर एक जिम्मेदार देश के तौर पर व्यवहार करने पर ही पाकिस्तान नया पाकिस्तान बन सकता है। नया पाकिस्तान का यह भी मतलब होगा कि वह आर्थिक और व्यापारिक मामलों में भारत से सहयोग चाहेगा। इमरान खान की पार्टी के घोषणा पत्र में चाहे जो कहा गया हो, उनमें वह क्षमता और योग्यता नहीं नजर आती कि वास्तविक बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर सकें। यह तो तय है कि तमाम राजनीतिक ड्रामे के साथ वह कुछ नया करते दिखेंगे, लेकिन इसमें संदेह है कि उसमें कुछ सार्थकता होगी। एक सफल क्रिकेट बनना अलग बात है और प्रधानमंत्री बनकर देश को नई दिशा देना अलग बात। इमरान खान नवाज शरीफ को मोदी का दोस्त बताकर ऐसे नारे के बीच उनकी आलोचना करते रहे हैं-जो मोदी का यार है वह गद्दार है- गद्दार है। भारत के बारे में उनके बयान भी यही बताते हैं कि वह सेना की लाइन पकड़े हुए हैं। वह भारत से सभी मसलों पर वार्ता करने के संकेत देंगे, पर बिना किसी नई पहल के। उनके नेतृत्व में पाक अपनी पुरानी सोच को ही दोहराता दिखेगा। भारत के खिलाफ आतंकियों का इस्तेमाल करने की नीति में कोई बदलाव होने के आसार नहीं। अगर इमरान सेना की भारत संबंधी नीति से हटना चाहेंगे तो वह इसे सहन नहीं करेगी। कुल मिलाकर भारत को पाकिस्तान में इमरान खान सरकार से किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं करनी चाहिए।

कुछ समय पहले इमरान खान की दूसरी पत्नी रेहम खान ने अपनी किताब में उनकी सोच और आदतों पर सवाल उठाते हुए काफी कुछ लिखा था, लेकिन उससे इमरान की सेहत पर असर नहीं पड़ा। पाकिस्तान में लोग यह सोचते हैं कि एक पूर्व पत्नी को ऐसा कुछ लिखना ही नहीं चाहिए। जो भी हो, रेहम खान की किताब इमरान के व्यक्तित्व को सामने लाती है। इमरान खान तमाम दावे कर रहे हैं, लेकिन लगता नहीं कि वह पाकिस्तान को सही दिशा दिखा पाएंगे। पाकिस्तान को मध्ययुगीन माहौल में ले जाने और हिंसा का सहारा लेने वाले किस्म-किस्म के इस्लामी समूह जिस तरह राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं उससे पाकिस्तान गलत राह पर ही जाता दिख रहा है। हालांकि पाकिस्तान ने आतंकी सरगना हाफिज सईद के राजनीतिक दल को मान्यता नहीं दी, लेकिन उसके समर्थक चुनाव लड़ने में समर्थ रहे। यह पाकिस्तान ही नहीं, पूरे क्षेत्र के लिए एक खतरनाक संकेत है।

(लेखक विदेश मंत्रालय में सचिव और पाकिस्तान डेस्क के प्रभारी रहे हैं)

response@jagran.com

लोकतंत्र में शरई अदालतों का क्या काम

नाइश हसन

मुस्लिम समाज के नेताओं को अपनी सोच और अपने रोल मॉडल, दोनों ही बदलने की जरूरत है

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हाल में न केवल यह कहा कि मुसलमान अपने मामले शरई अदालतों में निपटाएं, बल्कि यह भी ऐलान किया कि वह कुछ और ऐसी ही अदालतें खोलेगा। यह ऐलान ऐसे समय किया गया जब निकाह हलाला का मामला चर्चा में है। जब-जब मुसलमान औरतों ने धर्मसत्ता की जड़ों को हिलाने की कोशिश की है तब-तब ऐसी ही कोशिश हुई है। याद करें कि अतीत में जब शाहबानो, इमराना, गुड़िया या फिर शायरा बानो के मामले सामने आए तब शरीयत के हिसाब से चलने या फिर शरई अदालतें गठित करने अथवा उन्हें महत्व देने की पहल हुई। ऐसा जान पड़ता है कि नियंत्रण से बाहर होते गुलामों को फिर से नए हथियारों से साधा जा रहा है ताकि वे भागने न पाएं। देश के कई शहरों में दारूल कजा कही जाने वाली शरई अदालतें स्थापित की जा चुकी हैं। इन अदालतों ने कई मामलों में तीन तलाक को जायज ठहराते हुए फैसले दिए हैं। इसके सुबूत भी मौजूद हैं। खुला (पति से अलग होने का हक) लेने वाली औरतों को उनके सारे अधिकारों से वंचित करने वाले फैसले भी इन अदालतों ने दिए हैं। आज यह कहीं जरूरी है कि औरतों के सवाल को मानवाधिकार के प्रश्न के रूप में खड़ा किया जाए, न कि धर्मों के दायरे में। चूंकि भारत कोई इस्लामिक देश नहीं इसलिए धर्म आधारित अदालतें खड़ी करना अच्छे संकेत नहीं। शरई अदालतें एक शोषणकारी व्यवस्था की पैरोकारी से ज्यादा कुछ नहीं। भारत जैसे लोकतांत्रिक और पंथनिरपेक्ष देश में जहां अलग-अलग धर्मों, संस्कृतियों के लोग रहते हों, जहां आस्था की आजादी हो और जहां सबके निजी कानून भी हैं वहां जरूरत इसकी है कि इन निजी कानूनों में सुधार लाया जाए और उन्हें लैंगिक समानता के आधार पर बनाया जाए।

मुस्लिम महिलाएं तो यह चाहती हैं कि उन्हें समाज के हवाले न किया जाए, बल्कि उन्हें भारतीय संविधान के तहत गठित अदालतों से ही न्याय मिले। इन अदालतों में संतुष्ट न होने पर ऊंची अदालतों में अपील की गुंजाइश बनी रहती है परंतु दारूल कजा के फैसले की कोई अपील नहीं होती। दारूल कजा के फैसलों से दो-चार महिलाओं की दास्तान यह साफ कर देती है कि कैसे वे उनके हक में नहीं हैं। रेशमा नामक एक महिला इसलिए दारूल कजा गई, क्योंकि वह खुला चाहती थी। उसने वहां बताया कि पति बहुत मारपीट करता है इसलिए घरेलू हिंसा का केस कोर्ट में है, लेकिन मैं यहां खुला चाहती हूं। जवाब मिला, पहले आप वह केस उठाइए और हमें उससे संबंधित कागज दीजिए। रेशमा का कहना था कि दारूल कजा का सिस्टम ठीक नहीं। वहां बैठे लोग जैसे-तैसे औरत को मर्द के घर भेज देना चाहते हैं। औरत का पक्ष बिल्कुल भी नहीं

समझते। वे कुरान की रोशनी में नहीं, पितृसत्ता की रोशनी में फैसले सुनाते हैं। याद रहे तीन तलाक मसले पर पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से उच्चतम न्यायालय में औरतों को कमअक्ल बताया गया था।

2005-2006 में लखनऊ स्थित महिला संगठन तहरीक ने एक सर्वे कराया था जिसमें मध्य एवं निम्न वर्ग के लगभग 3500 मुस्लिम पुरुष और महिलाओं से बात की गई थी। इसमें एक सवाल यह पूछा गया था कि आप अपने किसी पारिवारिक विवाद के निपटारे के लिए कहां जाना पसंद करेंगे। जवाब में 79 प्रतिशत ने पुलिस और न्यायालय जाने की बात कही थी। जब यह पूछा गया कि क्या आपने दारूल कजा का नाम सुना है तो केवल एक फीसद लोगों ने हां में जवाब दिया था। क्या आप ने पर्सनल लॉ बोर्ड का नाम सुना है? इस सवाल पर हां कहने वाले लोगों का फीसद महज दो था। इस सर्वे में एक सवाल यह भी था कि क्या आप जानते हैं कि मसलक क्या होता है? इस पर सिर्फ पांच फीसद लोगों ने हां कहा था। जाहिर है कि दारूल कजा यानी शरई अदालतें लोगों की प्राथमिकता में नहीं हैं। आखिर जब इस तरह की अदालतों की मांग आम जनता ने नहीं की और जब किसी ने सरकार से यह अपील भी नहीं की कि हमारे न्यायिक हक की सुरक्षा के लिए किसी धार्मिक संगठन को जिम्मेदार बनाया जाए तब फिर शरई अदालतों के गठन का क्या मतलब? चूंकि सरकारों और राजनीतिक दलों ने वोट की सियायत साधने के लिए इस प्रकार के संगठनों को फलने-फूलने दिया इसलिए लोकतंत्र में हाशिये की आवाज का दम घुटता रहा। यह किसी से छिपा नहीं कि जमीयतुल उलमा ए हिंद, तबलीगी जमात, आला हजरत, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी तंजीमों ने संसद और न्यायपालिका में भी औरतों के सवाल पर तल्ख जुबानी की है। शरई अदालतों की जरूरत इसलिए नहीं, क्योंकि देश और दुनिया में शरीयत कानून एक से नहीं हैं। शरीयत में शिया-सुन्नी के कानून भी अलग हैं। एक लोकतांत्रिक देश में जबरदस्ती इस तरह का माहौल बनाना जिससे आम मुसलमान को भ्रमित किया जा सके, चिंताजनक है। यदि कल को हिंदू, ईसाई, पारसी आदि भी अपने निजी कानून होते हुए भी एक अलग न्याय व्यवस्था खड़ी करने लगें तो क्या परिणाम होंगे?

मुस्लिम समाज के नेताओं के पास कौम की चिंता के लिए बहुत से जरूरी सवाल हैं। उन्हें अपनी सोच और अपने रोल मॉडल यानी आदर्श, दोनों ही बदलने की जरूरत है। जिन अरब देशों की एक-एक बात को वे अकीदत से अपना लेना चाहते है उन्हें अगर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भेड़ें देना बंद कर दें तो वे हज में कुर्बानी भी नहीं दे सकेंगे। अमेरिका, यूरोप उन्हें गाड़ियां और विमान देना बंद कर दें तो वे घरों में कैद होकर रह जाएंगे। दुनिया के बेहतरीन 100 विश्वविद्यालयों में एक भी इस्लामिक दुनिया से नहीं है। जितने रिसर्च पेपर पूरे इस्लामिक देशों में निकलते हैं उससे ज्यादा रिसर्च पेपर अकेले बोस्टन शहर में निकलते हैं। अरब देशों ने बीते पांच सौ सालों में दुनिया को कोई नई दवा, नया तत्व ज्ञान, नया खेल, नया कानून, नया हथियार नहीं दिया। बावजूद इसके हमारी तंजीमें अरब देशों को रोल मॉडल मानकर हर वह गलती फख्र से करती हैं जो इन देशों के लोग कर रहे हैं। शरई अदालत स्थापित करके हम मुसलमानों को सदियों पीछे ले जाना चाहते हैं। इस्लाहे मुआशरा (समाज सुधार) के बहुत से काम करने बाकी हैं। उन पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। जब कौम को शिक्षित बनाने और उसमें चेतना पैदा करने का काम बाकी है तब कोर्ट-कचहरी खड़ा करने जैसा गैरजरूरी काम कौम को आगे लेकर नहीं जा सकता।

(लेखिका रिसर्च स्कॉलर और मुस्लिम वीमेंस लीग की महासचिव हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

विचार

इस उपलब्ध मानव जीवन में कर्म की गति, कर्म का स्वरूप और निषिद्ध कर्म-इन तीनों को जान लेना जरूरी है। इसके बाद सारी कामनाओं और संकल्पों से मुक्त होकर आगे बढ़ना चाहिए ताकि चित्त को शुद्ध बनाया जा सके। विचार में परिवर्तन होने से मनुष्य में परिवर्तन हो जाता है, उसका व्यक्तित्व बदलने लगता है। व्यक्तित्व बदलने से समाज और राष्ट्र में भी परिवर्तन हो जाता है। नतीजतन आप देख सकते हैं कि पूरा विश्व कहीं न कहीं युद्ध के कगार पर खड़ा है। राष्ट्रीय नेताओं और धार्मिक नेताओं के विचारों में कोई सामंजस्य नहीं रह गया है। समाज में अराजकता, अनाचार, अत्याचार और व्यभिचार चरम पर है। आज का मानव कहां भाग रहा है, दौड़ रहा है? उसे स्वयं पता नहीं। विचारों की दौड़ में सब एक दूसरे को मात देने में जुटे हैं। नैतिक पतन तेजी से हो रहा है। आपसी प्रेम और भाई चारा घृणा में कभी-कभी बदलता नजर आता है। अपनी आय से परेशन आज का मानव शांति की तलाश में इधर-उधर भटक रहा है, परंतु शायद यह विचार ठीक से नहीं कर पाता है कि यह उसे मिलेगी कैसे? शांति है कहां?

मनुष्य की बढ़ती कामनाएं, महत्वाकांक्षाएं उसे अशांति की तरफ जबरन ले जा रही हैं। बाहरी दुनिया की चकाचौंध के सामने वह अपने अस्तित्व को भूल गया है, अपने मूल स्रोत से कटकर रह गया है। इस प्रगतिशील विकासवाद की गोद में परमाणविक, रासायनिक अनुसंधान और भौतिक साज-सज्जा के समक्ष मनुष्य की शांति का मार्ग अवरुद्ध हो गया है। ऐसे में धर्म ही एकमात्र ऐसा मार्ग रह गया है, जो मनुष्य को शांति प्रदान कर सकता है। यदि विश्व के हर राष्ट्र और उसके नागरिक यह भली-भांति समझ लें कि उनका अपने प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र और विश्व के प्रति क्या उत्तरदायित्व है तो एक बार खुशहाली और प्रसन्नता पुनः वापस आ सकती है। यह समझ तभी आएगी, जब विचारों में परिवर्तन हो। धर्म एक व्यवस्था है जो संस्कृति और सभ्यता का निर्माण करती है। संस्कृति और सभ्यता से चरित्र का निर्माण होता है। जिसके निर्माण में योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। योग मन की चंचलता और चपलता को रोकते हुए हमारे अंदर अच्छे विचारों का प्रवाह कराता है। इसके द्वारा हमारे विचारों में ऐसा परिवर्तन हो कि हम परमात्मा में विलीन हो जाएं।

महायोगी पायलट बाबा

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

चुनाव से पहले हारी कांग्रेस

मोदी से मुकाबले की तैयारी शीर्षक से लिखे अपने लेख में प्रदीप सिंह ने 2019 के आम चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए विपक्ष की तैयारी पर प्रकाश डाला है। अगर किसी को अपने परिवार के पेशे या काम को अपनाना हो तो उसे बचपन से ही उसमें माहिर होने के लिए जी तोड़ मेहनत और उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में राहुल को कोई जिम्मेदारी का पद दिया होता और वह अपनी जिम्मेदारी पर खरे उतरे होते तो अपने पिता राजीव गांधी की तरह छोटी उम्र में ही प्रधानमंत्री बन जाते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए कांग्रेस मायावती और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर स्वीकार करने को तैयार होती दिख रही है। यहां कहना उचित होगा कि भाजपा के पास भी नरेंद्र मोदी के सिवाय दूसरा ऐसा कोई चेहरा ऐसा नहीं है जिसको आगे करके वह चुनाव लड़ सके। अगर होता तो प्रधानमंत्री को देश के हर राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए नहीं जाना पड़ता, लेकिन देश की सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी कांग्रेस के लिए यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसके पास अपनी पार्टी में प्रधानमंत्री पद का कोई योग्य चेहरा नहीं है। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने से पीछे हटना यह भी दर्शाता है कि कांग्रेस को अपनी साख बचाने के लिए और पार्टी के अच्छे दिन लाने के लिए बहुत ही मेहनत करने की जरूरत है। लगता है कि वह चुनाव से पहले ही हार गई है।

raju09023693142@yahoo.com

पाकिस्तान में कैसा लोकतंत्र ?

पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सत्ता बहाली के लिए मतदान कराए गए हैं। लेकिन ऐसे में मतदान का क्या फायदा जहां पहले से ही तय हो कि सरकार किसकी बनेगी। वास्तव में पाकिस्तान चुनाव में पाकिस्तानी सेना और वहां की आइएसआइ ने पहले से ही सत्ता की कमान सौंपने के लिए अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चुन लिया। दरअसल वहां का शासक वही बन पाता है जिसके साथ आइएसआइ और पाकिस्तानी सेना का साथ हो। इस बार पाकिस्तानी सेना ने अपने उम्मीदवार के रास्ते में आने वाले विरोधियों को पहले विभिन्न माध्यमों से हटा दिया। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को कोर्ट के माध्यम से चुनाव के लिए अयोग्य ठहरा दिया गया। उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। वहीं कुछ प्रांतों में उम्मीदवारों को डराया धमकाया गया। आजादी के बाद यह दूसरी बार होगा जब पाकिस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता के अपनाने की प्रक्रिया हो रही है।

नीरज झा, दिल्ली विश्वविद्यालय

सबको मिले समान अवसर

मराठा आरक्षण की आग में महाराष्ट्र जल रहा है। हम पहले भी गुर्जर, जाट, पाटीदार आरक्षण आंदोलन की आग को झेल चुके हैं। लेकिन कोई भी सरकार या दल सबक लेने को तैयार नहीं है। जब सब एक हैं तो यह आरक्षण की बैशाखी क्यों ? सबको समान अवसर क्यों नहीं? कब तक देश आरक्षण के नाम पर जलता रहेगा ? आरक्षण खत्म कर सबको समान अवसर मिले यह वक्त का तकाजा है।

hemlataupadhya42728@gmail.com

हिंसा के लिए स्थान नहीं

लोकतंत्र में सरकार तक अपनी बात पहुंचाने और गलत बातों का विरोध करने की हर किसी को आजादी है। लेकिन इसमें हिंसा का कोई स्थान नही है। अगर कोई इस आजादी का दुरुपयोग कर जान और माल के नुकसान पर उतर आए तो ऐसे लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

सतीश त्यागी काकड़ा, गाजियाबाद

...ताकि कोई भूखा न रहे

दिल्ली के मंडावली इलाके में तीन मासूम बच्चियों की मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। ये मौतें मुखमरी के कारण हुई हैं और वह भी देश की राजधानी में। कोई सोच भी नहीं सकता कि जहां लोग कामकाज के लिए आते हैं, वहां कोई खाने को भी मोहताज होगा। ऐसा माना जाता है कि यहां कोई भी काम करके व्यक्ति अपनी रोजी रोटी चला सकता है। लेकिन इस घटना ने इस विश्वास को तोड़ दिया है। वास्तविकता क्या है, यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन बच्चियों की मौत खाने के अभाव में हुई है। इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुई है। भारत में अनाज की पैदावार में कोई कमी नहीं है। हर साल लाखों टन अनाज बरसात में सड़ जाता है, लेकिन जरूरतमंद तक अनाज नहीं पहुंच पा रहा है। आजादी के बाद से भारत विश्वपटल पर नए आयाम स्थापित कर रहा है, वहीं दूसरी ओर गरीबी एवं भुखमरी जैसी मूलभूत समस्याओं से निपटने में नाकाम रहा है। वर्ष 2017 में प्रकाशित रिपोर्ट में 119 देशों में भारत का 100वां स्थान यह पुष्टि करता है कि इस विषय में हमें लम्बा रास्ता तय करना है। संयुक्त राष्ट्र ने भी भारतीय स्थिति को चिंताजनक बताया था। दक्षिण एशियाई देशों से तुलना करने पर भी भारत स्वमं को भुखमरी, कुपोषण एवं शिशु मृत्यु दर में अपने पड़ोसी बांग्लादेश, नेपाल सरीखे देशों से पीछे ही पाता है, परन्तु यह देश का दुर्भाग्य ही है कि आज भी यह किसी राजनैतिक दल के एजेंडे में प्रबल रूप से शामिल नहीं है। हालांकि सरकार ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के सहारे इसमें कुछ दिलचस्पी जरूर दिखाई थी, परंतु प्रश्न यह है कि धरातल पर यह योजनाएं कितने प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं? बरसात में अनाज के सड़ने की खबर शायद ही मस्तिष्क से निकलती होगी। जरूरत है ऐसी योजना कि जिससे कोई भूखा न रहे।

kkumarnishant@gmail.com

ट्वीट-ट्वीट

इमरान खान ने अपनी विदेश नीति की प्राथमिकताओं व चुनौतियों को गिनाते हुए भारत को पांचवें स्थान पर रखा। चीन, अफगानिस्तान, अमेरिका व सऊदी अरब के बाद। वह भी हमारे मीडिया पर नाराजगी दिखाते हुए। यह क्रम हमारे लिए अच्छा है या चिंताजनक, यह भविष्य बताएगा। पर कश्मीर का जिक्र तो पुराने ढर्रे पर ही है।

राहुल देव@rahuldev2

शपथ से पहले इमरान खान कह रहे हैं 'मैं बंगला नहीं लूंगा जी'।

डॉ. कुमार विश्वास@DrKumarVishwas

1981 में जनरल जिया उल हक ने ही नवाज शरीफ को पाकिस्तान का वित्त मंत्री बनाया था। तब वह पाकिस्तानी सेना की आंखों के दुलारे थे। अब तल्ख तेवरों वाले इमरान को समर्थन देकर सेना एक तरह से इतिहास ही दोहरा रही है। भले ही जो जीते पाकिस्तान में सत्ता पर पकड़ तो सेना की ही बनी रहेगी।

मेजर गौरव आर्या@majorgauravarya

वृक्षारोपण गलत शब्द और अवधारणा है। असल में हम एक पौधा रोपते हैं। यह पौधा तभी पेड़ बनता है जब हम 20, 30 या 40 साल तक उसका खयाल रखते हैं। पौधा रोपना महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे एक पेड़ बनाना उससे 20, 30 या 40 गुना बड़ी जिम्मेदारी है।

अतुल कुलकर्णी@atul_kulkarni

जनपथ

दिल्ली में ही भूख से मरीं बेटियां तीन,
रहो बजाते प्रगति की आप बैठकर बीन।
आप बैठकर बीन सुरीला गाकर गाना,
भूखा मरे गरीब मयस्सर ना हो दाना।
बड़े शर्म की बात उड़ रही चहुंदिश खिल्ली,
पर मस्ती में चूर 'आप' की अपनी दिल्ली।

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित, संपादक (दिल्ली एनसीआर) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, **E-mail: delhi@nda.jagran.com,** R.N.I. No 50755/90 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। वर्ष 29 अंक 10